

झालाना डूंगरी स्थित कल्ली के भट्टों वाली सरकारी जमीन पर

लगा यह कोर्ट स्टे का बोर्ड असली है या फर्जी?

जिस सरकारी जमीन को पहले भी अतिक्रमण मुक्त करवा चुके

उसे फिर से खाली करवाने में देरी क्यों?

भाग-4

आखिर किस बहाने से ज़ोन-1 के प्रवर्तन अधिकारी

जेडीए के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक महोदय को गुमराह कर रहे हैं?

भूमाफियाओं की दबंगई से सरकार के आदेश भी दरकिनार!!!

जेडीए के ज़ोन 1 में स्थित झालाना डूंगरी,बाईजी की कोठी,दूरदर्शन केंद्र के पास स्थित सरकारी जमीन का मामला

जेडीए के ज़ोन 1 में स्थित झालाना डूंगरी,बाईजी की कोठी,दूरदर्शन केंद्र के पास स्थित सरकारी जमीन पर बरसों से भू-माफियाओं की गिद्ध द्रष्टि गढ़ी हुई है।विगत 10 सालों में इस सरकारी जमीन पर कई बार बस्तियाँ बसाने की कोशिशें की जा चुकी हैं और कई बार जेडीए इन अवैध बस्तियों को उजाड़ भी चुका है।परंतु भूमाफियाओं और जेडीए के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से हर कार्यवाही के बाद इस सरकारी जमीन पर बस्तियाँ बस जाती हैं।

परंतु इस बार भूमाफियाओं द्वारा बड़े सुनियोजित तरीके से इस जमीन पर कब्जे किए जा रहे हैं।जिसकी भनक जेडीए के जिम्मेदार अधिकारियों को भी है।अब इस सुनियोजित साजिश से लगता है कि अब जेडीए के अधिकारियों का हिस्सा भी तय हो चुका है।तभी तो लाख शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार सोये हुए हैं और अतिक्रमी धड़ाधड़ अतिक्रमण कर,अवैध निर्माण कर रहे हैं।

स्टे का बोर्ड सही या फर्जी?

हमारे द्वारा यह मामला जेडीए के संज्ञान में लाने पर जेडीए के जिम्मेदार अधिकारी तोते की तरह यही रटा-रटाया जवाब दे रहे हैं कि मामले में जिम्मेदारों को जेडीए की धारा 72 के तहत नोटिस जारी किए जा चुके हैं।दिनांक 17/05/2021 को दिये गए जवाब में भी ज़ोन-1 के प्रवर्तन अधिकारी यही बात दोहरा रहे हैं।लेकिन अभी तक अतिक्रमण हटाने की बात पर मौन है।जानकारों के अनुसार इस मामले में जेडीए के प्रवर्तन अधिकारियों और संविदा पर तैनात कर्मचारियों की भूमाफियाओं से साँठ-गाँठ सामने आ रही है।अपने आला अधिकारियों द्वारा इस मामले में जवाब मांगने पर वह इस प्रकरण में किसी कोर्ट-स्टे का हवाला देकर मामला टालने में लगे हुए हैं।लेकिन स्टे किस कोर्ट का है? कब लगा है?इसकी जानकारी देने से कतरा रहे हैं।



मौके पर लगा कोर्ट स्टे का बोर्ड।

Jaipur Development Authority (J D A) , Enforcement Officer . (Enforcement) , Enforcement Officer - 1	...	Remarks	17-May-2021	प्रकरण में धारा ७२ के नोटिस जारी किये जा चुके हैं अधिकारवाही प्रक्रियांचिन है
Jaipur Development Authority (J D A) , Enforcement Officer . (Enforcement) , Enforcement Officer - 1	...	Partially Closed :Relief	17-May-2021	प्रकरण में धारा ७२ के नोटिस जारी किये जा चुके हैं अधिकारवाही प्रक्रियांचिन है



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-1/2021/डी- 1564


दिनांक 19/7/24

मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन),
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय:-व्यापक जनहित में जेडीए के जोन-1 में बाईजी की कोठी, दूरदर्शन के पास (कल्ली के भट्टो की सरकारी जमीन), झालाना डूंगरी स्थित करोडो रुपये की सरकारी जमीन को भूमाफियाओं द्वारा किये गये कब्जों/अतिक्रमण/अवैध निर्माणों से मुक्त कर तारबंदी करने बाबत प्रार्थना पत्र।

सन्दर्भ:-नगरीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, का डायरी क्रमांक 33882 दिनांक 21.06.2021 के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत जोन द्वारा जाँच परीक्षण कर अतिक्रमण को चिन्हितकरण कर भिजवाया गया है जिसमें नियमानुसार कब्जे/अतिक्रमण/अवैध निर्माण को हटाने का श्रम करावें।



(कुन्तल विश्नोई)
उपायुक्त, जोन-1
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-)

1/ जवाब दो सरकार, एस-1, सेंकड फ्लोर, झारखण्ड अपार्टमेंट, झारखंड महादेव मोड, जनरल सगत सिंह मार्ग, खातीपुरा, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

इस सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार के निर्देशों की भी पालना नहीं।

इस मामले में जेडीए द्वारा उदासीनता बरतने पर हमारे द्वारा यह मामला राज्य सरकार के संज्ञान में भी लाया गया था, जिस पर सरकार द्वारा जेडीए को कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे। इस मामले में जेडीए जोन -1 की उपायुक्त श्रीमति कुन्तल विश्नोई द्वारा मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन को पत्र लिख कर अतिक्रमण को चिन्हित कर नियमानुसार कब्जे/अतिक्रमण/अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश दिये लेकिन कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी है।


(कुन्तल विश्नोई)
उपायुक्त, जोन-1
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 302 004
फोन : 0141-2573150 (0) 0141-2574555 (F) e-mail : jdc.jda@rajasthan.gov.in



प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिये गए धारा 72 के नोटिसों के बावजूद निर्माण कार्य जारी|,सड़क,बिजली की सभी व्यवस्थाएं चालू|

जवाब मांगते सवाल?

1. आखिर ज़ोन-1 के प्रवर्तन अधिकारी इस करोड़ों रुपयों की सरकारी जमीन से अतिक्रमण खाली करवाने की कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं?
2. उनके द्वारा धारा 72 के नोटिस जारी किए हुए 7 महीने से अधिक हो गए हैं उसके बावजूद वह इस मामले की फाइल क्यों दबाये बैठे हैं?
3. क्या इस जमीन पर किसी कोर्ट का स्टे है?यदि स्टे है तो क्या जेडीए उस संबन्धित मामले में पक्षकार है?यदि स्टे है तो जेडीए इस स्टे को रद्द करवाने की पुरजोर कोशिश क्यों नहीं कर रही?
4. यदि यह स्टे झूठा हुआ तो क्या झूठ बोलने वाले प्रवर्तन अधिकारी और उनके संविदा कर्मियों पर कार्यवाही की जाएगी?
5. जब जेडीए की प्रवर्तन शाखा रोज अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने का दावा कर रहा है तो इस सरकारी जमीन से आँख क्यों फेरे हुए हैं?
6. कौन है यह भू-माफिया जो बार बार इस जमीन पर पट्टे काट कर लोगों को बेच रहा है?आखिर उसके विरुद्ध कोई सख्त कार्यवाही क्यों नहीं कर रहा जेडीए?
7. इस मामले में संबन्धित प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महोदय को क्या तथ्य बता कर गुमराह किया जा रहा है?
8. ज़ोन-1,प्रवर्तन शाखा के संविदा कर्मियों की इस मामले में क्या मिलीभगत है?
9. आखिर क्यों जेडीए के जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में राज्य सरकार द्वारा दिये गए निर्देशों की भी पालना नहीं कर रहे हैं?
10. आखिर क्यों इस ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी महोदय को लाख शिकायतों के बावजूद नहीं हटाया जा रहा है?